

18-38 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION  
FOREIGN BANKS IN INDIA

श्री श्रीचंद गोयल (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, बैंकों के सम्बन्ध में जिस प्रश्न में से आधे घण्टे की यह चर्चा निकली है उस का उस समय दायरा बहुत सीमित था। केवल यह पूछा गया था कि अपने देश में कितने विदेशी बैंक काम कर रहे हैं और उन के डिपॉजिट्स की रकम कितनी है। अपने देश में 13 विदेशी बैंक हैं जिन का 483 करोड़ रुपये का डिपॉजिट है। आज सरकार की तरफ से जो "स्टेटिस्टिकल टेबल रिपोर्टिंग टु बैंक इन इंडिया" नाम की जो पुस्तक है उस में मैंने कुछ आंकड़े देखने का प्रयत्न किया। उस से पता चला कि अनेकों इस प्रकार के बैंक हैं, जैसे नेशनल फ्रिडलेज बैंक, जिन का डिपॉजिट 186 करोड़ से अधिक है, जिस का वार्षिक लाभ 80 करोड़ के लगभग है। उसी प्रकार फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक के एसेट्स 81 करोड़ से ज्यादा के हैं। हमारी सरकार ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण का निश्चय किया तो क्या उसने एक राजनीतिक प्रश्न इसको बना कर किया और इसी कारण से विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया। हो सकता है कि उनके दिमाग में एक विचार यह आया हो कि हमने दूसरे देशों को कुछ आश्वासन दिये हुए हैं और उनको पूरा किया जाना चाहिये। उनके हमारे देश के अन्दर बैंक हैं और उन बैंकों को निबंधन रूप से कार्य करने की स्वतन्त्रता रहनी चाहिये। यह भी हो सकता है कि हमारी सरकार के मन में यह विचार आया हो कि यदि हमने इन विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो दूसरे देशों में हमारे जो बैंक कार्य कर रहे हैं, उनके साथ भी वहां की सरकारें बदले की भावना से कार्य करें और उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दें। हो सकता है कि हमारी सरकार के दिमाग में यह विचार भी आया हो कि विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण

करने से विदेशी पूंजी भारत में लगना कहीं बन्द न हो जाये। अगर विदेशी पूंजी के लगने के बारे में सरकार के मन में सन्देह उत्पन्न हुआ था तो क्या वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया था कि अमरीका के आजूबत ने यह बात कही थी कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने का अर्थ यह हर्गिज नहीं है कि यहां पर विदेशी अपना सरमाया नहीं लगायेंगे। उन्होंने कहा था कि हमने ऐसे देशों के अन्दर, फ्रांस आदि में जिन्होंने कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है, अपना योगदान दिया है और वहां भी विदेशी सरमाया और विदेशी पूंजी बराबर लगाई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि चूँकि उनके दिमाग में यह एक राजनीतिक प्रश्न था, क्या यही कारण था कि उन्होंने विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया और अपने देश के अन्दर चलने वाले देशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके एक भेदभावपूर्ण नीति बरती या इसके अन्दर कोई कानूनी अड़चनें महसूस की ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने इस मामले में कोई कानूनी राय जांचने की कोशिश की थी। हमारे देश को अनेकों और भी इस प्रकार की स्थितियों का मुकाबला करना पड़ रहा है जैसे मलेशिया के अन्दर उन्होंने भारत के जो तीन बैंक काम करते हैं, उनका राष्ट्रीयकरण कर लिया है। मैं समझना चाहता हूँ कि क्या हमारी सरकार के दिमाग में यह प्रश्न एक राजनीतिक प्रश्न के रूप में उपस्थित हुआ था ? क्या उसने यह सोचा कि विदेशी बैंकों का अगर राष्ट्रीयकरण किया गया तो उससे कुछ कानूनी अड़चनें पैदा हो सकती हैं ?

जहां तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि उस में इस प्रकार का कोई संकेत नहीं है कि कानूनी अड़चन सरकार के रास्ते में आ सकती थी अगर विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता। मैं जानना चाहता हूँ कि हमने जो अपने देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और इनको छोड़ा तो इसका

क्या परिणाम निकला ? इसको किए हुए कुछ महीने बीत चुके हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार इस स्थिति में होगी कि जो उसने सारी स्थिति का मूल्यांकन किया है, उससे वह इस सदन को अवगत करा सके। जो जायजा उसने लिया है, उससे मैं चाहता हूँ कि इस सदन को अवगत कराया जाए। आज तक जो परिणाम निकले हैं, वे हमें बताये जायें। जब से हमने अपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है, तब से क्या यह सही है कि जो सरमाया है वह विदेशी बैंकों की तरफ दौड़ने लग गया है और क्या यह भी सही नहीं है कि उनके अन्दर कुछ ज्यादा हिसाब खुले हैं। यदि यह सही है तो इस पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में भी किसी प्रकार का कोई पग उठाया जाएगा ?

मैं ने एक वक्तव्य पढ़ा था जिस में कहा था जिस में कहा गया था कि विदेशी बैंकों को बिना भारतीय बैंकों के मुकाबले में आए, बिना उन से स्पर्धा किये, अपनी शाखायें खोलने की ज्यादा छूट मिल गई है। जब राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय इन सारी स्थितियों के बारे में सन्देह प्रकट किया गया था और कहा गया था कि इसका नतीजा यह भी निकल सकता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की कास्ट पर विदेशी बैंक फले फूलेंगे, उनकी ज्यादा शाखायें खुलें, उनके पास ज्यादा हिसाब आयें और हमारे बैंकों का सरमाया भी उनकी तरफ दौड़े मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले महीनों का इनका अनुभव इसके बारे में क्या रहा है ?

काजी कमेटी मुकर्रर हुई है इस बात का अनुमान लगाने के लिए या इस बात को तय करने के लिए कि जो तेरह विदेशी बैंक हमारे देश में चल रहे हैं उनका कोई एक संस्थान बन सकता है या उनका कोई एक इंस्टीट्यूशन बनाया जा सकता है।

मंत्री महोदय इस पर भी प्रकाश डालें कि

काजी कमेटी के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है और क्या उस ने कोई इन्टेरिम रिपोर्ट पेश की है या नहीं।

भारत में विदेशी बैंकों को छूट देने का ज्यादा उद्देश्य यह था कि विदेशों के साथ हम व्यापार करते हैं और एक्सचेंज के सिलसिले में उन बैंकों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। मैं समझता हूँ कि उस का अर्थ तो केवल इतना ही होना चाहिए था कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास प्रादि भारत के बड़े बड़े बन्दरगाहों में उन बैंकों की शाखायें होतीं। लेकिन आँकड़ों को देखने से पता चलता है कि एक एक बैंक की पचास पचास शहरों में शाखायें हैं और बम्बई में तो एक ही बैंक की अनेक शाखायें हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि देश भर में उन विदेशी बैंकों की शाखाओं का जो जाल बिछा हुआ है, क्या भारत सरकार उस पर कोई प्रतिबन्ध लगाने और उन शाखाओं को कुछ कम करने का विचार कर रही है या नहीं। क्या सरकार ने कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगाने का निश्चय किया है कि विदेशी बैंक भविष्य में अपनी शाखायें न खोल सकें, भविष्य में उन के हिसाब न बढ़ सकें या दूसरे बैंकों का सरमाया उन के पास न जा सके ? क्या सरकार ने इस सिलसिले में कोई पग उठाये हैं, या क्या वह ऐसे कोई पग उठाने का विचार रखती है ?

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में सरकार की इस भेदभाव की नीति के कारण देश में यह विचार पैदा हुआ है कि शायद किसी राजनैतिक दबाव में आ कर, या किसी राजनैतिक विचार को दृष्टि में रख कर, सरकार ने विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया। मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में भारत सरकार की नीति भविष्य में क्या रहेगी।

[श्री श्री चन्द गोयल]

कहा जाता है कि रिजर्व बैंक की तरफ से यह डायरेक्टिव जारी किया गया है :

"Permitting foreign banks in the country to open new accounts and branches without offering competition to Indian banks."

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सबमुच इस प्रकार का कोई आदेश रिजर्व बैंक की तरफ से जारी हुआ है ; अगर हाँ, तो क्या भारत सरकार उस पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार होगी। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के साथ साथ विदेशी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण करना चाहिये था, क्योंकि उन के पास बड़ी पूंजी है, उन को बड़ा वार्षिक लाभ होता है, उन की शाखाओं का जाल सारे देश में फैला हुआ है और वे अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या पिछले चार पांच महीनों के अनुभव के आधार पर सरकार अब इस नतीजे पर पहुंची है कि विदेशी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण करना देश के हित में होगा ? अगर यहाँ के बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना देश के हित में था, तो क्या विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना भी देश के हित में है या नहीं ; अगर है, तो फिर सरकार किन दिक्कों के कारण उन का राष्ट्रीयकरण नहीं कर रही है ?

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : Sir, these foreign bankers, especially the British ones which have a predominant business in this country, are guided by the policy laid down by the London Institute of Bankers which is confined to merchant banking, simply money-lending, and has no obligation to follow your policy in this country, while operating, they give preferential treatment to foreign-controlled firms. While giving advances, they do not bring their own capital; they are using the Indian depositors' money to borrow and

lend. The PL 480 funds are going to give these foreign-controlled banks an added advantage over the counterparts controlled by Indians.

These foreign banks are dens of over-involving and underinvolving performances which may be costing us Rs. 300 to Rs. 400 crores a year in foreign exchange. I am drawing the attention of the Minister to the famous case which took place in Calcutta, involving the National and Grindlay's Bank and several officials. I am also drawing attention to the B. N. Eillas and Company case' and the case where fake medical students names are created for remittance of foreign exchange through Hong Kong. Then there is silver smuggling which goes on between Indian and other countries. Dubai is the centre of these foreign banks operating in India and running their offices; they are the greatest participants in this smuggling business. They take out money from this country by showing head office charges. Why should they be allowed to take out this money ? They have been allowed to open new branches. Government has allowed them to bring into existence new branches in Calcutta. The minister must tell us whether it is a fact that National and Grindlays Bank have opened a new branch in Calcutta. If I remember aright, it is in Southern Avenue.

I want to know whether it is also a fact that the restriction that was there on opening of new branches by foreign banks has been removed a couple of years ago and, if so, what is the reason ? Then, they do not maintain separate figures for foreign exchange banks and Indian banks in the international business. Why is it so ? Then my demand is that these banks should be nationalised immediately. Till such time these banks should be restricted wholly and fully in their business.

श्री रमधीर सिंह (रोहतक) : पहला तो सवाल मैं यह पूछना चाहूँगा कि यह बैंक जो हैं यह एक प्रिविलिज्ड इंस्टीट्यूशन तो नहीं बन गए हैं ? क्या इन बैंकों के सरमाये को भी देश के नेशनल डेवलपमेंट के लिए या रूरल डेवलप-

मेंट के लिए सोशल कंट्रोल करके किसी प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है ? जैसे नेशनलाइज्ड बैंक हैं, उन से कर्जा लेने की सहूलियत है वैसे ही इन से भी हो सकता है क्या ? यह बैंक किसी खास प्रिविलिज्ड क्लास के लिए ही तो नहीं रहे जैसे पहले दूसरे बैंक हुआ करते थे ?

दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इन बैंकों को नेशनलाइज न करने से आप के जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं उन पर कोई अच्छा असर पड़ा है या पुरा असर पड़ा है ? अगर बुरा असर पड़ा है तो उस के लिए क्या कर रहे हैं ?

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर इन को नेशनलाइज नहीं करते, या तो इन को नेशनलाइज करो, अगर नेशनलाइज नहीं करते तो क्यों नहीं करते ? और नहीं करते तो सोशल कंट्रोल इन का करदो ताकि देश के हित के लिए यह काम आ सकें ।

श्री रवि राय (पुरी) : विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सिलसिले में हम लोग पहले से जो सरकार के खिलाफ आरोप लगाए हैं उस के दो पहलू हैं । एक तो पहलू है जैसा आप जानते हैं हमारा दो तिहाई इलाका देश का पिछड़ा है । जैसे नासिर साहब ने एक ऐतिहासिक काम 1956 में किया कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया, भले ही इंग्लिस्तान, इज्रायल और फ्रांस की सरकार का हमला उस के कारण उस के ऊपर हुआ लेकिन एक ऐतिहासिक काम उन्होंने किया लेकिन इस सरकार ने विदेशी बैंकों और विदेशी राष्ट्रों के दबाव में आकर यह जो चीज थी कि विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती, वह नहीं किया । क्या इस में यह झलक नहीं आती है कि सुप्रिम कोर्ट के विचार के बाद यह पसपात हो रहा है कि इंडियन बैंकों का

राष्ट्रीयकरण तो कर दिया, ठीक किया लेकिन विदेशी बैंकों को क्यों छोड़ दिया ?

दूसरा मुद्दा यह है कि जैसे बर्ड एंड कम्पनी है, इन का नीदरलैंड बैंक है, यह बर्ड एंड कम्पनी हमारे देश को लूट रहे हैं और इन का एकाउंट नीदरलैंड बैंक में रहता है, हम जानना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में जितने विदेशी बैंक काम करते हैं इन का कौन कौन विदेशी फर्मो से ताल्लुक रहता है और क्या इन का धोरा है और क्या मंत्री महोदय देश में बैंक राष्ट्रीयकरण के सिलसिले में जो एक वातावरण बन गया है उस को देखते हुए यह बतायेंगे कि कब तक, किस ध्रुवधि तक हिन्दुस्तान में विदेशी बैंकों की जो शाखायें हैं उनका राष्ट्रीयकरण करेंगे ? उन का राष्ट्रीयकरण करने के सिलसिले में कब तक कदम उठायेंगे ?

श्री बेनी शंकर शर्मा (बाँका) : मैं जानना चाहता हूँ हमारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से पहले क्या संसार के और कितने देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनसे शायद हमारे मंत्री महोदय को बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रेरणा मिली ? अतएव क्या माननीय मंत्री जी उन देशों के नाम बतायेंगे जिन्होंने अपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के साथ साथ विदेशी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया तथा उन देशों का भी जिन्होंने केवल अपने ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, एवं विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया ?

मेरा दूसरा प्रश्न है कि आपने अभी बताया था कि कई ऐसे कारण हैं जिन की बजह से आप विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते हैं । मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आप उन का राष्ट्रीयकरण नहीं कर रहे हैं उस उद्देश्य की प्रति के लिए अर्थात् विदेशी व्यापार की सुविधा के कारण क्या उन

[श्री रवि राय]

बैंकों की ब्रांचों की जो आज शहरों और गाँवों में खुली हुई हैं, कोई आवश्यकता है। क्या मंत्री जी कम से कम उन को बन्द कर सिर्फ पोर्ट्स पर ही उन की ब्रांचे रहें ऐसी व्यवस्था करेगी।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : The matter before the Supreme Court relating to discriminations against the banks which were nationalised had mainly two aspects—firstly, these fourteen banks were prohibited after the acquisition of their undertaking from carrying on banking business; secondly, there was no reasonable basis for the selection of fourteen banks as against the other Indian banks and foreign banks for the acquisition of their undertaking and that there was no reasonable nexus between the selection and the object sought to be achieved by the Act. As far as the first point is concerned, as the hon. House is aware, we have amended the Act in the light of the Supreme Court decision. So far as the second point of hostile discrimination against the said banks is concerned, the Supreme Court left the issue open by saying that “in the absence of reliable data we do not think it is necessary to express an opinion on the question whether the selection of the undertakings of some out of the many of the institutions for compulsory acquisition is liable to be struck down as hostile discrimination”. So, the Supreme Court itself has not given any decision on this point in its judgment. While they were very clear in their decretal opinion as far as hostile discrimination with regard to not allowing these banking companies to carry on their banking business is concerned, on the other point they did not pronounce any judgment because they said that the relevant data is not before them. In view of the Supreme Court not having given any decision on that point, we thought it wise not to enlarge the scope of the nationalisation which was earlier decided by the government and was also approved by the hon. House.

As far as the question of not taking the foreign banks in the category of nationalised

banks is concerned, I think we have advanced the arguments a number of times as to why foreign banks could not be nationalised. For the benefit of the House, I would like to enumerate the main reasons why the foreign banks have not been nationalised. The foreign banks are part of the worldwide organisation and their international connections enable them to give better facilities in regard to foreign trade than most of the Indian banks.

SHRI JYOTIRMOY BASU : Then why did you nationalise foreign life insurance companies? Don't give cock and bull stories all the time.

SHRI P. C. SETHI : We are talking of banks, not of life insurance companies.

SHRI JYOTIRMOY BASU : Both of them are financial institutions.

SHRI P. C. SETHI : Then, foreign banks undertake certain items of business of a specialised nature. For instance, the bank of Netherlands specialises in financing the export of jewellery and import of uncut diamonds etc. Foreign banks also assist raising foreign currency loans and also assist entrepreneurs to contact parties overseas equipped with technical know-how. Several foreign firms of long standing have close relationship with officers of the foreign banks operating in India. As Shri Goyal has rightly pointed out, there is also the question of reciprocity in the matter of foreign banks because we have branches of our banks in United Kingdom and Japan.

Then Shri Goyal raised the question of the branches which we have got in Malaysia. Sir, the Malaysian Government has not nationalised them. On the contrary they have allowed them to function for the time being. We approached them with a request to continue them but the position or the character of the banks there will have to be altered, and we are in negotiation with the Malaysian Government in order to amend the whole situation in accordance with the existing practice and law. Therefore, the statement that they have been nationalised there is not correct.

I would also like to deny the fact that Government were acting under some pressure.

19 hrs.

श्री रवि राय : एक तरफ बाप कहते हैं कि सेल्फ सफिशिएन्ट बनें और दूसरी तरफ कहते हैं कि फारेन कैपिटल फ्लो करेगा तो इसका क्या मतलब है ?

SHRI P. C. SETHI : Self-sufficiency is the object. It does not necessarily mean that in a hurry we should jump over it. We have to approach it with caution and see that national interest is not hampered. I would like to deny that there was any pressure whatsoever. We had no agreement whatsoever with regard to this point and the nationalisation of foreign banks was not done because of any pressure. It was on account of these considerations which were in the national interest that we had done so.

With regard to the position of flight of capital, I would like to point out as far as the foreign banks are concerned in the deposit as on July 18, 1969 with foreign banks there is only a rise of 1.5%, that is, 7.2 crores. It was 481.9 crores on 18th July, 1969 whereas on 27th March, 1970 it was 489.1 crores. As far as the State Bank Group is concerned, there is a rise of 10.9%. It was 1248.1 crores on July 18, 1969 whereas on March 27, 1970 it was 1384.7 crores—an increase of 136.6 crores. With regard to 14 nationalised banks the position on July 18, 1969 was 2686.2 crores whereas on 27th March, 1970 it was 2814.7 crores—a rise of 188.6 crores or 7.2%. Therefore, as compared to the rise in the 14 nationalised banks and the State Bank Group we can confidently say there is no flight of deposits either from the State Bank Group or from the nationalised banks to the foreign banks. Therefore, Sir, the fear that there will be flight of deposits from the nationalised banks to the foreign banks is not correct, and on the country we are moving on a definite line which was quite expected. In the initial stage the Reserve Bank had issued an Informal direc-

tive to them not to encourage any flight of deposits and they have persistently adhered to this policy.

Shri Randhir Singh also asked whether the Reserve Bank had any control over these banks. As far as the lending and borrowing policies are concerned, they are governed by the Reserve Bank as is done in the case of other banks. Then Sir, Mr. Jyotirmoy Basu raised the question of head-office charges of these banks and he said they are also being remitted as part of the cost of these banks. It is a fact that in some cases head office charges are being remitted.

SHRI JYOTIRMOY BASU : How much per year ?

SHRI P. C. SETHI : I do not have that break-up. As far as the profits of these banks are concerned it is true, as compared to the total deposit—Mr. Goyal raised this point—their profits are high. This is on account of the nature of business they are carrying on.

SHRI JYOTIRMOY BASU : They are taking Indian deposits, doing business and making a lot of profit, and taking the money home.

SHRI P. C. SETHI : On account of the nature of the business, it is a fact that the profits are high and, along with the profits, they remit a certain part of the expenses to the head offices which they are doing.

As far as the question of opening new branches is concerned, now the policy is, except in the port towns, in the interior they are not allowed to open new branches. Whatever branches they have opened in the interior, except in the port towns, were opened before. Now they are not allowed to open new branches in the interior of country. They are allowed to open new branches in the port towns but that is also subject to the permission of the Reserve Bank of India.

SHRI JYOTIRMOY BASU : What about opening of the new branch of the National Grindlays Bank in Calcutta at Southern Avenue? This is after the nationalisation of the banks.

SHRI P. C. SETHI : I have not said that they are stopped from opening branches. In the port towns, with the permission of the Reserve Bank, they are, certainly, allowed to open branches in the port towns, not in the hinterland.

SHRI JYOTIRMOY BASU : Are you maintaining separate accounts, separate figures, showing the quantity of international business handled by foreign banks and the Indian banks and if not, the reasons therefor?

श्री रवि राय : बाद में दे दीजियेगा ।

SHRI P. C. SETHI : I do not have the detailed information in regard to this particular point. If the hon. Member desires it and, if it is permissible under the present Reserve Bank rules, I will certainly furnish the information.

As far as the question which was raised by Shri Goyal and Shri Rabi Ray concerned, whether we are going to nationalise these banks sometime in the future, whether we have fixed any target date, I can not predict as to what will happen in the future. The present policy of the Government was just announced and it was discussed in the House twice and there we have stated that we are not nationalising the foreign banks on account of the factors that were given. As long as it is in the

interest of our country, we shall certainly follow the present policy. If the interest of the country is going to be hampered, certainly it is always open to the Government and to the Parliament to change it. But for the time being, I do not envisage any change in the present policy.

श्री रवि राय : हमारा सवाल यह था कि बड़े एंड कम्पनी का नीडरलैंड्स बैंक में अकाउंट रहता है। और उसी तरह से भिन्न भिन्न बैंकों को कम्पनियों में अकाउंट रहता है।

SHRI P. C. SETHI : It will be very difficult for me to do within this short time. I do not have all the accounts as to which of the foreign banks... (Interruptions)

SHRI JYOTIRMOY BASU : What about under-invoicing and over-invoicing? They are their creation. They are detts of under-invoicing and over-invoicing.

SHRI P. C. SETHI : I could realise Mr. Jyotirmoy Basu is an expert on the subject. I would certainly like to be briefed on this subject so that I can take advantage of his long experience. Sir, I have explained the present position and I have nothing more to add.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 A.M.

19.09 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, April 28, 1970/Vaisakha 8, 1892 (Saka)*

---